'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

प्रकाशन तिथि- 31 मई, 2014

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, क्लॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 17 ● अंक 14 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 1 से 15 जून, 2014

परिसंघ का राष्ट्रीय सेमिनार 6 जुलाई को हैदराबाद में

डॉ0 उदित राज

जिन परिस्थितियों में मैंने संसद पहुंचने का फैसला लिया, अधिकतर परिसंघ के लोग जानते और समझते हैं। मैं उत्तर पश्चिम दिल्ली से चुनकर लोकसभा में पहुंचा हूं। इसमें मेरी व्यक्तिगत इच्छा या संतुष्टि बाद में है और मुख्य उद्देश्य दलित, आदिवासी और वंचित समाज की भागीदारी पहले। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के समय भी यही प्रतिबद्धता मैंने दुहराई थी और यह पूरा जीवन रहेगा। संसद में पहुंचने का मतलब तभी साकार होगा जब परिसंघ के लोग काम को और तेज करेंगे। अकेले भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली है जबकि मुद्दा आरक्षण या दलित उत्थान आदि चुनाव में नहीं बन पाया था। किसी भी पार्टी का मुद्दा चुनाव में आरक्षण या दलित सशक्तिकरण नहीं था। जब बिना आरक्षण और दलित अधिकार की बात उठे बिना सत्ता में पहुंचा जा सकता है तो मैं कितना पार्टी और संसद में कर सकूंगा जब तक कि सामाजिक आंदोलन तेज न हो। इस बार मेरे आंदोलन के साथियों ने भाजपा को चुनाव में पूरा समर्थन किया है और उसका पुरस्कार मिलना चाहिए ऐसा मैं समझता हूं। भाजपा में शामिल होने से पहले मेरी प्रमुख शर्त यही थी कि दलित समाज को भागीदारी हर क्षेत्र में मिले, वह भाजपा का पूरा साथ देगा और एक बार नहीं बल्कि लगातार।

परिसंघ अकेले गत् 17 साल से आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहा है लेकिन अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। केवल ब्राह्मणवाद की आलोचना करना आंदोलन समझ लिया जा रहा है जबकि यह गलत है। हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है और जिनके हाथ में देश की धन-संपत्ति और सत्ता है उसका साथ देकर विभिन्न क्षेत्र में भागीदारी लेना है। नई आर्थिक नीति की वजह से आरक्षण घटा है। सामाजिक आंदोलन यदि तेज होता है तो हम विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी के लिए स्वयं सक्षम हो जाएंगे। आरएसएस के कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव को देखकर मैं कह सकता हूं कि हमारे साथी उनकी तुलना में कुछ भी नहीं हैं। जहां से मैं चुनाव लड़ा, मैंने अनुभव किया कि आरएसएस के कार्यकर्ता साढ़े पांच और छः बजे शाखा में पहुंचते थे और प्रार्थना के बाद प्रत्येक घर जाकर प्रचार करते थे। उन्होंने निश्चय किया था कि प्रत्येक घर तीन बार प्रचार के लिए जाना है और ऐसा उन्होंने किया भी जो मेरी जीत का बड़ा कारण था। दूसरी तरफ मेरे साथी यदि अपने अंदर झांककर के देखें तो क्या कहीं पर ये टिकते हैं? आरएएस का यह समर्पण अनुकरणीय है। हमारे साथी साल में रैली में एक बार पहुंच जाएं तो उसके लिए वह बड़ी बात मानी जाती है। आरएसएस की तरह समर्पण भाव की भावना मैं अपने साथियों में देखना चाहता हूं।

परिसंघ को फिर से नई गति देने का समय आ गया है और इसलिए इस बार का राष्ट्रीय अधिवेशन 6 जुलाई, 2014 को रवींद्र भारती ऑडिटोरियम, हैदराबाद में रखा गया है। यह कार्यक्रम आंध्रप्रदेश के परिसंघ के अध्यक्ष श्री महेश्वर राज के संरक्षण में हो रहा है, उनसे संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर :- 09440508869 है।

साथियों से अनुरोध है कि 5 जुलाई को पहुंचे ताकि 6 जुलाई के अधिवेशन में भाग ले सकें। 7 जुलाई को प्रमुख लोग बैठकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। लोग वापसी 7 जुलाई की शाम या 8 जुलाई की सुबह करेंगे।

...

प्रधानमंत्री को जानो

डॉ0 उदित राज

6 जून, 2014 को प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने लोक सभा में कहा कि पैर छूने से काम नहीं चलेगा, काम करना होगा। पार्टी के सांसदों को सीख दी कि वे पूरी तैयारी से संसद में आएं। 11 जून को उन्होंने नौजवानों को हुनर (स्किल) सीखने के लिए आवाहन किया। उन्होंने कहा भारत देश भाग्यशाली है कि उसकी 60 प्रतिशत आबादी जवान है उनकी उम्र 35 वर्ष से कम है, जबकि चीन बूढ़ा हो रहा है। अंग्रेजों ने पढ़ने-लिखने वाली शिक्षा को स्थापित किया, क्योंकि उनको ऐसी ही आवश्यकता थी। उन्हें इस देश में विकास करने की कम, शासन-प्रशासन में सहयोग करने वाले डिग्रीधारियों की ज्यादा जरूरत थी। आज़ाद भारत के बाद हमे शिक्षा को अपनी आवश्यकता के अनुसार ढालना चाहिए था लेकिन ऐसा हो न सका।

मैंने जब कालेज से पढ़कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तब पैर छूने की संस्कृति का बड़ा गहरा अनुभव हुआ। पढ़ाई-लिखाई खास होती नहीं थी। छात्र राजनीति चरम सीमा पर थी। जो नेता जितना अधिक परीक्षा आगे बढ़वा सके वही सफल माना जाता था। परिणाम यह हुआ कि सत्र तीन साल पीछे चल रहा था। पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गयी थी। इनमें से अधिकतर छात्र नेता पैर छुआने और छूने में माहिर थे। जब कभी प्रोफेसर या विश्वविद्यालय के अधिकारी मिलते तो ये छात्र नेता गुरुजी प्रणाम कहते हुए पांव छू लेते थे और उनके चले जाने पर अक्सर भद्दी गालियां देते थे। इन छात्र नेताओं का भी पैर छूने वाले छात्रों की कमी नहीं थी। उस समय अनुभव हुआ कि किसी को सम्मान हृदय से ही सही रूप से दिया जा सकता है, क्योंकि पैर छूने वाला जरूरी नहीं है कि अंदर से भी सम्मान करता हो। पैर छूना बड़े काम की चीज है। लोग इस कृत्य से सांसद और विधायक बनते हैं। कुछ समय पहले एक सांसद ने अपना रहस्य बताया कि 5 साल तक काम करने की जरूरत नहीं है, जब चुनाव आता है तो मुझे वोटरों का चेहरा नहीं, बल्कि पांव ही दिखता है। चुनाव के समय दिन भर में हजारों लोगों के पैर छू डालता हूं, इस तरह से लोग खुश होकर माफ कर देते हैं। आरक्षित सीटों पर यह ज्यादा ही है लेकिन वोटर भूल जाते हैं कि वे अपने को ही सजा दे रहे हैं। पांव छूकर काम चलाने वाले नेता विकास नहीं करेंगे तो क्षेत्र पिछड़ेगा और बर्बादी उस क्षेत्र के सभी लोगों की होगी। प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि काम करने से देश तरक्की करेगा न कि चमचागीरी से।

प्रधानमंत्री ने 'स्किल, स्केल एंड स्पीड' का नारा दिया है। 11 जून को उन्होंने लोक सभा में एक बीती हुई घटना का जिक्र किया। एक बार विनोवा भावे ..... से एक स्नातक का छात्र मिला, उससे जब उन्होंने पहली बार पूछा कि तुम क्या जानते हो? उसने कहा कि मैं स्नातक हूं, दुबारा पूछा तो फिर वही जवाब और चार बार उसका जवाब ऐसा ही रहा। इस उद्धरण का मतलब कि उस छात्र के हाथों में कोई हुनर नहीं था, जो कि कुछ कर सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वे गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो स्किल प्राप्त कर रहे छात्रों को भी उसी तरह की डिग्री मिली, जो सामान्य स्कूल और कॉलेज में होता है। ..... इस तरह से स्किल को सम्मान तो मिला ही साथ-साथ उसके प्रयोग से देश की तरक्की भी होगी। असंगठित क्षेत्र में 93 प्रतिशत कामकाजी अप्रशिक्षित हैं। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन का लक्ष्य 2022 तक 500 मिलियन अर्थात 50 करोड़ को स्किल्ड बनाना है। जिस तरह से प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति है, उससे इसको पूरा करने में मुश्किल नहीं आनी चाहिए।

जब मैं अध्ययन कर रहा था तो कई बार मन में सवाल आए कि क्यों नहीं हमारे यहां इंजीनियरिंग में सिविल, मैकेनिकल, मेटलरजी, इलेक्ट्रिकल जैसे विषय का आविर्भाव हुआ। भारत में सर्वप्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्थापित हुआ था। यदि प्रशिक्षित या हुनर वालों को हमने सम्मान दिया होता तो तमाम विषयों का आविष्कार हो जाता। लोहे से काम करने वाले को लोहार तो कहा गया लेकिन उसके स्किल अथवा ज्ञान को सम्मानित किया गया होता तो वह और रुचि रखता और धीरे-धीरे जैसे यूरोप में धातु, जैसे लोहा आदि पर जो कार्य किए उन्होंने मेटलरजी विषय को जन्म दिया। जिनको मकान बनाना आता था उनके हाथों और ज्ञान को समाज में सम्मान और अच्छा मेहनताना मिला और इससे सिविल इंजीनियरिंग का आविर्भाव हो गया। विकसित देशों में मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन आदि को घंटे के हिसाब से पढ़े-लिखे के बराबर वेतन मिलता है, जबकि हमारे यहां बहुत अंतर है। स्किल डेवलपमेंट से न केवल रोजगार की समस्या का समाधान होगा बल्कि ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति होगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पांव छूने से काम नहीं चलेगा बल्कि कड़ी मेहनत करनी होगी। इससे राजनीति में एक नई संस्कृति का आगाज होता दिखता है। स्पष्ट संदेश है कि चमचागीरी से काम नहीं चलेगा बल्कि विकास करना होगा। जरूरत नई राजनैतिक संस्कृति (पोलिटिकल कल्चर) की है, जिससे जन प्रतिनिधि ज्ञान और क्षमता से युक्त हों। इससे स्वाभाविक रूप से उनमें विकास करने का दृष्टिकोण पनपेगा। इस तरह से किसी भी राजनीतिक दल के अच्छे कार्यकर्त्ताओं को आगे आने का मौका मिलेगा। चेला पालने की प्रथा खत्म करना जरूरी है। बड़े नेताओं के पांव छूकर और सेवा देकर तमाम फायदे और टिकट आदि लिए जा रहे हैं तो कर्त्तव्यपरायण, ईमानदार, ज्ञान और प्रशासक होने की क्या जरूरत है? न केवल रोजगार लेने के लिए बल्कि नए पोलिटिकल कल्चर के लिए भी स्किल प्राप्त करनी है। सदियों से भारत देश की यह आवश्यकता है और प्रधानमंत्री इसे पूरा करना चाहते हैं। चीन के लोग भी बड़े सुस्त और पाखंडी हुआ करते थे लेकिन माओत्से तुंग के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से सांस्कृतिक क्रांति की उससे चीनियों की सोच बदल गयी। यह संदेश भी उसी दिशा को इंगित करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आम लोगों को सहयोग भी देना पड़ेगा, अगर दिया तो हमारे देश में भी कठिन परिश्रम करने की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा जो बहुत दिनों से अपेक्षित है।

...

सामाजिक क्रांति के लिए टोपी नहीं खोपड़ी बदलनी होगी

एस. एल. सागर

एक सच्चाई यह है कि इस भारी-भरकम गजकाय अद्विज समाज ने स्वयं संगठित होकर कभी ऐसा चिंतन नहीं किया कि वे स्वयं उठे, अपना दीपक स्वंय बने और संगठित होकर अपने शोषण के विरूद्ध जेहाद बोलें। जिसे स्वयं अपनी हालत सुधारने का सलीका न आता हो उसकी हालत सुधारने कोई दूसरा नहीं फिर शोषक तो बिल्कुल ही नहीं क्योंकि शोषक दयाहीन होता है। यदि इस समाज ने कभी संगठित होकर समाज बदलने का प्रयास किया होता और अपना 1-2 प्रतिशत इस कार्य में लगाया होता तो वह भूखा-नंगा पीड़ित समाज काफी उठ गया होता और उसकी तस्वीर बदल गयी होती। वास्तविकता यह है कि ऐसा इन्कलाब वह समाज कर पाता है कि जो स्वावलंबी होता है। किंतु यह समाज तो पहले से द्विजों का माना हुआ गुलाम रहा है, जो मानसिक रोग से पीड़ित हो, अपने जन्म-मरण, विवाह तक बिना द्विजों के परामर्श कभी न करता हो और उसकी कृपा के लिए प्रार्थनाएं करता हो। उस समाज का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उसका पढ़ा-लिखा तबका वकील, डॉक्टर, इंजीनियर भी पुरोहितों के चक्कर में पड़ा रहता है। पुरोहितों के गुमराह करने पर उस रामचरित मानस का पाखंड पाठ कराता रहा जिसके लिए उसमें आदेश दिया गया है कि ''ढोल गंवार शूद्र पशु नारी- ये सब ताइन के अधिकारी'' और उस गीता का प्रवचन कराता रहा जिसमें शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से बताई गयी है। यह बेचारा शूद्र इन ग्रंथों के वचनों से लांघा गया नीच बना समाज की बेड़ियों से जकड़ा रहा और मानसिक रूप से ऐसा गुलाम बन गया कि वर्णवादी सोच के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सका। इस भारी भरकम समाज का पढ़ा-लिखा आदमी काफी संख्या में नौकर पेशा बन गया है जो स्वतंत्रता के बाद ही पढ़-लिख सका था। ये अपनी काबिलियत के आधार पर ऊंचे पदों पर भी पहुंचा है किंतु यह अंधविश्वासी है उसे अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं हुआ, अपने द्विज महानों की कृपा मानता रहा। इस पढ़े-लिखे तबके में एक कमी और रही कि व्यक्तिगत रूप से तो ये लायक थे किंतु सामाजिक रूप से नालायक थे। इस समाज का पढ़ा-लिखा मानसिक रोगी तबका बुद्धि और धन की ऊर्जा अपने समाज के विकास में न लगाकर मठ मंदिर में दान देने, कथा-भागवत कराने और देवी-देवता भूतों के पूजन में लगा रहा।

इस दलित-पिछड़े समाज के छात्र स्कूलों में ब्राह्मणवादी लेखकों के पुराणवादी साहित्य पढ़ते हैं और इन्हीं से तैयार किए गए प्रश्न पत्रों के उत्तर परीक्षाओं में लिखते रहे इसलिए उनका प्रारंभिक सोच पुराणवादी बना रहता है जो इतनी गहराई तक घर कर जाता है कि शिक्षा समाप्त करने के बाद वे जीवनभर उसी सोच को ढ़ोते रहते हैं। वास्तव में शिक्षा का कोर्स समाजवादी और समतावादी होना चाहिए। इसके लिए ब्राह्मणवादी द्विज सोच के कारण किसी सरकार ने कोर्स नहीं बदला। अब तक जो पाया गया है उससे यही सिद्ध होता है कि अद्विज समाज का राजनैतिक प्रतिनिधि सबसे गए-बीते सोच का व्यक्ति होता है जो पहले तो पढ़ा-लिखा ही कम होता है दूसरा वह अति भीरू होता है। उसके भीरू बने रहने का कारण द्विज वर्ग का मत प्राप्त करना होता है। इसलिए किसी दलित-पिछड़े राजनैतिक प्रतिनिधि से किसी प्रकार के इंकलाब की मांग करना निर्मूल है। हमें यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि भारत की सत्ता में जो दल रहे वे सभी मनुवादी रहे हैं और इनमें जो आरक्षित सीटों से आए दलित वर्ग के विधायक-सांसद रहे, वे सब द्विजों की कृपा से ही चुनकर आए। क्रांति सदैव सोच के साथ चलती है। क्रांति का वाहन सोच होता है बाहरी आवरण नहीं। चोला नहीं चरित्र क्रांति का सिंबल है। क्रांति धनवान और बाहुबली नहीं करते, बुद्धिजीवी करते हैं जो टोपी नहीं खोपड़ी बदलने का काम करते हैं।

विज्ञान से दुनिया के हर वैज्ञानिक द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि इस धरती का मानव समुदाय विभिन्न मानव नस्लों का समूह है। जिन नस्लों का वर्गीकरण जलवायु रक्त एवं शरीर रचना (पिगमेंटेशन) के आधार पर किया गया है। भारत के दलित और पिछड़ों का रक्त और पिगमेंटेशन एक है इसलिए इनका डीएनए एक है और द्विजों के डीएनए से भिन्न है। यह उन लोगों का है जो ऊष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लोग हैं। यह पूरा कर्क और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र है। हम यहां यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) का डीएनए एक है जो और एशिया के लोगों से मिलता है। इस प्रकार से यह प्रमाणित तथ्य है कि दलित और पिछड़े एक नस्ल के हैं और भारत के मूल निवासी है जबकि अन्य भारत भूमि पर विदेशी है, बाहर से आए हैं।

जो आर्य इस देश में मध्य एशिया के शीत मैदानी इलाके से चरवाहे के रूप में आए तो भारत जैसी उपजाऊ हरियाली युक्त भूमि स्थल थे और मनुष्य को खाने के लिए तीन-तीन ऋतुओं में पैदा होने वाले अनेक किस्म के अन्न थे। हमलावर आर्यों में सभी सैनिक चरवाहे पुरुष थे। नारियां इनकी बाद के जत्थों में आई। वह भी बहुत कम अर्थात स्त्रियां 10-15 प्रतिशत से अधिक नहीं थी। आर्य यहां कई जत्थों में भारत में आए। अपने अनुकूल जलवायु देखकर वे यहीं स्थायी रूप से बस गए। जब इन्होंने यहां के मूल निवासियों की धन-दौलत को लूट कर उस पर कब्जा करना शुरू किया तो घोर आर्य मूलनिवासियों संघर्ष करना शुरू कर दिया। इस संघर्ष में आर्यों ने छल-कपट का सहारा लिया और धोखा देकर तमाम अनार्य राजाओं को मार डाले और उनकी विधवाओं को अपनी रखैलें और पत्नियां बना ली। इतना ही नहीं प्रारंभ में एक-एक अनार्य नारी कई-कई आर्यों की पत्नी बनी। जब आर्यों की संख्या निरंतर बढ़ती गई तो आर्यों के स्वंय के बीच भूमि के झगड़े बढ़ गए। कुछ लोगों की मान्यता है कि महाभारत की कहानी उसी झगड़े की जड़ है। यह कहानी भी प्रारंभिक छोटे कहानी से हो सकती है। कृष्ण वैदिक अनार्य राजा है। आर्यों के दो गुटों के भूमि के लिए लड़ना और कृष्ण द्वारा दोनों का विनाश कर देना वैदिक काल की घटना हो सकती है।

आर्यों के भारत में स्थायी रूप से बसने के बाद यहां के मूल निवासियों को गुलाम बनाने के लिए तमाम प्रकार के काले नियम-कानून गढ़ने शुरू कर दिए। इन कानूनी नियमों का उल्लंघन दंडनीय अपराध बना दिया गया। यहां के मूल निवासियों को टुकड़ों में बांटने की नीयत से चार वर्णों और चार हजार जातियों के टुकड़ों में बिखेर दिया। मूल निवासी रंग के काले थे और आर्य गोरे इसलिए इनमें विभाजन स्पष्ट था। वर्ण व्यवस्था में गोरे आर्य द्विज बन गये और काले वर्ण के मूल निवासी शूद्र वर्ण में धकेल दिए गए। आर्यों के तीन वर्ण ब्राह्मण बुद्धि, क्षत्रिय बाहु और वैश्य धन बल का मालिक बन गया तथा परजीवी बनकर शूद्र के श्रम पर सवार हो गया। शूद्र सेवक वर्ग था, वह श्रमजीवी था और ऊपर के तीन वर्णों का दास/सेवक था। विद्या पर ब्राह्मण का कब्जा था और शूद्र के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद थे। बाहुबल पर क्षत्रिय का अधिकार था। शूद्र के लिए शस्त्र धारण करना निषेध था जबकि अस्त्र-शस्त्र क्षत्रीय की जन्म कुंडली के साथ रखे जाते थे। धनबल का मालिक वैश्य था। सोना-चांदी उसकी तिजोरियों में बंद रहता था लेकिन शूद्र को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। उसकी संपत्ति केवल कुत्ते और गधे हो सकते थे। यदि कोई शूद्र कुछ धन संग्रह करता तो राजा को उसका धन छीन लेने का अधिकार था। शूद्र का सोना धारण करना दंडनीय था।

शेष अगले अंक में...

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रों के लिए
निःशुल्क उच्च शिक्षा का बेहतरीन मौका

आर्थिक कठिनाइयों के कारण दलित छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जो चिंता का विषय है। अजा/जजा परिसंघ के रा0 चेयरमैन, डॉ0 उदित राज जी, सभी शिक्षण संस्थानों से अपील करते रहे हैं कि वे अपने यहां दलित छात्रों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करके अपने सामाजिक दायित्वों को निभाएं। इसी क्रम में भगवान महावीर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन डॉ0 संजय जैन ने वायदा किया है कि वे अपने संस्थान में यथासंभव दलित छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देंगें। इनके संस्थान में निम्नलिखित उच्च शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की सुविधा है -

B.Arch, Polytechnic Diploma, B.Tech, M.Tech, BBA, BCA, D.Ed.,
JBT, B.Ed., M.Ed., B.Pharma, M. Pharma, C.Ped, B.P.Ed., M.P. Ed.

contact
(A Group of Jain Minority Institutions)
Bhagwan Mahaveer Group of Institutions
(Approved by AICTE, New Delhi, Ministry of HRD, Govt. of India,
& Affiliated to DTE, Haryana and DCR University of Science & Technology
Murthal, Sonepat (Haryana))
For Admission & Other details Visit at www.msitsnp.in or Contact :-
Prof : (Dr.) Sanjay Jain, Chairman, M.- +91-9810628607
Prof : (Dr.) O. P. Sharma, Registrar, M.- +91-8607400783 &

Hostel facility available on payment basis.

चीन भी मुस्लिम विखंडनवाद से लहूलुहान है

विष्णु गुप्त

भस्मासुर को संरक्षण दोगे, भस्मासुर पैदा करोगे तो उसका परिणाम भी तो भुगतोगे? कुआं दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए खोदा जाता है। जिस पाकिस्तान में आतंकवाद नाम के भस्मासुर को चीन ने संरक्षण दिया था, अप्रत्यक्ष समर्थन दिया था उसी आतंकवादी हिंसा से आज चीन खुद दग्ध है। इस्लामिक आतंकवाद ने आज चीन की राष्ट्रीय एकता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है। चीन में भी कश्मीर, चेचन्या की तरह विखंडन, संहारक आतंकवादी प्रक्रियाएं बेकसूर लोगों को लहूलुहान कर रही हैं। चीन को अगर इस्लामिक हिंसा और इस्लामिक विखंडन की प्रक्रिया से मुक्ति पानी है तो फिर उसे विश्वव्यापी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ वैचारिक और अभियानी पथ पर चलना ही होगा क्योंकि दुनियाभर के मुस्लिम आतंकवादी एक-दूसरे के पूरक हैं और सहयोगी भी हैं, सभी का लक्ष्य आतंकवादी हिंसा के बल पर दुनिया में इस्लाम का झंडा फहराना है और दुनिया में मुस्लिम मजहबी कानून लागू करवाना है। दुनियाभर में जारी इस्लामिक आतंकवाद के मूल्यांकन पर यह तथ्य सामने आता है कि राजनीतिक, मजहबी विखंडनवाद की प्रक्रिया पहले शुरु होती है और उसके बाद आतंकवाद की प्रक्रिया शुरु हो जाती है। कश्मीर से लेकर रुस के चेचन्या तक एक लंबी फेहरिस्त है जहां पर पहले राजनीतिक-मजहबी विखंडनवाद की प्रक्रिया शुरु हुई और उसके बाद आतंकवाद की प्रक्रिया शुरु हुई। चीन के शिनजियांग में पहले राजनीतिक, मजहबी विखंडनवाद की प्रक्रिया चल रही थी और अब शिनजियांग आतंकवाद से लहूलुहान हो चुका है। कई मुस्लिम आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में तीन सौ से ज्यादा लोग मारे गए हैं, कई सौ लोग घायल हो चुके हैं। मुस्लिम आतंकवादी हिंसा के दमन के लिए चीन को कड़ी और प्रहारक सैनिक-पुलिस कार्रवाई का सहारा लेना पड़ा है। चीन का कहना है कि उसके यहां जो मुस्लिम हिंसा-आतंकवाद की जड़ है उसके लिए वैश्विक मुस्लिम आतंकवादी सरगनाएं और मजहबी संस्थाएं जिम्मेदार रही हैं। चीन खासतौर पर पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी को जिम्मेदार मानता है। पाकिस्तानी तालिबान और अलकायदा की उपस्थिति भी शिनजियांग में है। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी के आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर है। आतंकवादी शिनजियांग में आतंकवाद का कहर बरपा कर पाकिस्तान में शरण ले लेते हैं, इस कारण चीन प्रहारक तौर पर मुस्लिम आतंकवादियों के खिलाफ अभियान नहीं चला पाता है। 2003 में पाकिस्तान सेना के अभियान में पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के सरगना हसन माहसूम की मौत हुई थी। हसन माहसूम के संबंध में कहा जाता है कि वह अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन का भी निकटवर्ती था। हसन माहसूद की मौत के बाद आतंकवादी संगठनों ने शिनजियांग को और अधिक निशाना बनाया है। आतंकवादी संगठनों की समझ है कि चीन के कहने पर पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के नेता हसन माहसूद को सैनिक अभियान में मार गिराया था। इसी कारण आतंकवादी सरगना शिनजियांग में आतंकवादी हिंसा की आग झोंक रहे हैं।

शिनजियांग में तुर्की मूल की मुस्लिम आबादी की बहुलता है। जिस देश में भी मुस्लिम आबादी की थोड़ी-बहुत भी ऊंची संख्या हो गयी, उस देश में अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग ही नहीं बल्कि इस्लामिक शासन लागू करने की मांग यानी विखंडन की राजनीतिक मजहबी प्रक्रिया शुरु हो जाती है और फिर आतंकवादी हिंसा भी चरम पर पहुंच जाती है। कश्मीर में मुस्लिम बहुलता के कारण अलग देश की मांग हो रही है और इस निमित आतंकवादी राजनीतिक मजहबी विखंडन की हिंसा जारी है। रुस के चेचन्या में मुस्लिम आबादी बहुमत में है वहां पर भी अलग मुस्लिम देश और मजहबी कानून को लागू करने के लिए आतंकवाद जारी है। म्यांमार के सिर्फ एक क्षेत्र में मुस्लिम आबादी बहुलता में नहीं है फिर भी वहां पर मुस्लिम आतंकवाद जारी है और मुस्लिम आतंकवाद से म्यांमार की बौद्ध संस्कृति लहूलुहान है। फिलीपींस में मुस्लिम आतंकवाद की जड़ में मुस्लिम देश की मांग है। नाईजीरिया में कड़े इस्लामिक कानून की मांग को लेकर बोको हरम मानवता को शर्मसार करने वाली हिंसा का खेल खेल रहा है। बोको हरम ने 500 से अधिक ईसाई बच्चियों का अपहरण कर लिया जिनकी आयु आठ वर्ष से लेकर 14 वर्ष की थी। अपहृत ईसाई बच्चियों को बोको हरम ने अरब के शेखों और अफ्रीकी धनाढ्य वर्ग के लोगों को बेच कर जेहाद के लिए पैसे जुटाए हैं। अपहृत लड़कियों का पता लगाने में अमरीकी खोजी विमान अभी तक अभियान पर है। इसी तरह चीन के शिगजियांग में तुर्की मूल की मुस्लिम आबादी की बहुलता है। तुर्की मूल की मुस्लिम आबादी चीन से अलग होकर एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए जेहाद कर रही है। शिनजियांग में चीनी प्रतीकों के सर्वनाश का भी जेहाद चला है। दो साल पूर्व शिनजियांग में मुस्लिम आबादी और चीन के समर्थकों के बीच में बड़ी हिंसा हुई थी, दंगे की आग में शिनजियांग कई दिनों तक जला था। उस दंगे की आग को चीन ने सैनिक, पुलिस कार्रवाई कर बुझा दिया था।

चीन भस्मासुर है। चीन के सिर पर मुस्लिम आतंकवाद और मुस्लिम हिंसा का जो खेल जारी है उसके लिए चीन खुद जिम्मेदार है। चीन का सैनिक और कूटनीतिक साझेदार पाकिस्तान है। चीन ने ही पाकिस्तान को आण्विक शक्ति बनाया है। भारत को दबा कर रखने की नीयत से चीन ने पाकिस्तान के मुस्लिम आतंकवाद पर न केवल मुंह मोड़ा था बल्कि पाकिस्तान की तरफदारी भी की थी। जब भी भारत द्वारा पाकिस्तान पर आतंकवाद का कारखाना चलाने का आरोप लगाया जाता था या फिर विश्व समुदाय द्वारा पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठती थी तब चीन पाकिस्तान के संरक्षक के तौर पर खड़ा हो जाता था। उसकी समझ यह थी कि पाकिस्तान भारत और विश्व के अन्य क्षेत्रों में आतंकवाद का आउटसोर्सिंग जरूर कर सकता है पर उसके यहां पाकिस्तान आतंकवाद की आउटसोर्सिंग नहीं कर सकता है। चीन के सामने समस्या यह है कि आतंकवादी संगठन बेलगाम हैं, अनियंत्रित हैं, पाकिस्तान का नियंत्रण या फिर लगाम आतंकवादी संगठनों के ऊपर नहीं रही। आतंकवादी खुद पाकिस्तान के लिए खतरा बने हुए हैं। हमें यह भी देखना होगा कि आतंकवादी संगठनों का लक्ष्य क्या है? आतंकवादी संगठनों का लक्ष्य दुनिया में आतंकवादी हिंसा के बल पर इस्लामिक राज्य की स्थापना और अन्य सभी धर्मो को नेस्तनाबूद करना है। ऐसी प्रक्रिया का हल भी सतही तौर पर नहीं हो सकता है। चीन को इन तथ्यों पर गौर करने की जरूरत है कि पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व हो सकता है कि आतंकवाद विरोधी हो पर पाकिस्तान की सेना और आईएसआई पूरी तरह से अभी भी आतंकवाद का खेल खेल रही हैं। जब तक पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और आतंकवादियों में नेटवर्किंग जारी रहेगी तब तक चीन ही क्यों दुनिया के अंदर आतंकवादी हिंसा कहर बरपाती रहेगी।

चीन अगर यह सोच रहा होगा कि वह शिनजियांग की मुस्लिम आबादी को थोड़ी बहुत राजनीतिक छूट और मजहबी अधिकार की छूट देकर मुस्लिम आतंकवादी हिंसा का समाधान कर लेगा तो यह उसकी खुशफहमी ही है। शिनजियांग की मुस्लिम आबादी को चीन ने कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं। मजहबी अधिकारों की छूट दी है। एक नहीं बल्कि दो बच्चे पैदा करने की भी छूट दी है। मुस्लिम आबादी को छोड़कर अन्य चीनी नागरिक सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। अन्य चीनी नागरिक धर्म को मानने के अधिकार नहीं रखते हैं, अन्य चीनी नागरिकों को अपने धर्म प्रतीकों की पूजा करने का अधिकार नहीं है। पर मुस्लिम आबादी मस्जिद जाकर नमाज पढ़ सकती है। सार्वजनिक तौर पर भी मुस्लिम आबादी अपने मजहबी त्यौहार मना सकती है। इन सभी राजनीतिक और मजहबी अधिकारों की छूट के बावजूद भी शिनजियांग में मुस्लिम अलगाव और मुस्लिम विखंडन की प्रक्रिया क्यों नहीं रुक रही है? इस पर चीन को विचार करने की जरूरत है। विश्वव्यापी मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ स्वार्थपरक कूटनीति जब तक जारी रहेगी तब तक मुस्लिम आतंकवाद और मुस्लिम विखंडन की प्रक्रिया जारी रहेगी। चीन को इस तथ्य को समझना होगा?

साभार : पंजाब केसरी

EDUCATE! ORGANISE!! AGITATE!!!
NSOSYF
NATIONAL SC, ST, OBC STUDENT & YOUTH FRONT
चार दिवसीय
राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर
17 जुलाई से 20 जुलाई, 2014
स्थान : डॉ0 अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड,
वीडियोकॉन टॉवर, झंडेवालान, नई दिल्ली
डी. हर्षवर्धन (राष्ट्रीय समन्वयक) 07709975562
रवि प्रकाश (उत्तर भारत समन्वयक) 08881677448
साबरी व्ही (दक्षिण समन्वयक) 08881677448
T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 011-23354841-42, Telefax: 011-23354843
E-mail : h.dawane2013@gmail.com/ Facebook.com/harshavrdhandawane

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of '**Justice Publications**' at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

'नसोसवायएफ' की राष्ट्रीय चिंतन बैठक दिल्ली में संपन्न

बालाजी कोंडामंगल

नेशनल एससी, एसटी, आबीसी स्टूडेंट्स एंड यूथ फ्रंट (नसोसवायएफ) उत्तरी भारत की राष्ट्रीय चिंतन बैठक अंबडकर भवन, नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक में उत्तरी भारत के दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक के प्रथम सत्र में उत्तरी भारत में नसोसवायएफ की स्थिति के बारे में जानकारी ली गयी। निजी क्षेत्र में आरक्षण हेतु रैली की तैयारी, राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए आगामी नवंबर की रैली में दो लाख छात्र एवं युवाओं को जंतर-मंतर पर इकट्ठा करना, आदि बिन्दुओं पर इस बैठक में गहरी चर्चा की गयी। नसोसवायएफ के नेशनल को-ऑर्डिनेटर डी. हर्षवर्धन ने इस सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स एंड यूथ फ्रंट जातिविहीन समतामूलक समाज के निर्माण के लिए एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण के आंदोलन को तेज करने का प्रयास करेगा। नसोसवायएफ की जरूरत और उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा कि आजादी के बाद अब तक दलित, आदिवासी और ओबीसी छात्र एवं युवाओं को संगठित करने का न तो प्रयास किया गया और न ही अब तक इस दलित, आदिवासी और ओबीसी का कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया गया और ऐसा करने की किसी ने जरूरत भी महसूस नहीं किया। इसी की कमी को पूरा करने और दलित, आदिवासी और ओबीसी के छात्र एवं युवाओं के आर्थिक और सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए नसोसवायएफ का गठन किया गया।

चिंतन शिविर में डॉ0 उदित राज व हर्षवर्धन के साथ एनएसओएसवाईएफ के पदाधिकारीगण

इस बैठक के द्वितीय सत्र को नसोसवायएफ के मुख्य मार्गदर्शक डॉ. उदित राज ने संबोधित करते हुए कहा कि नसोसवायएफ एक अंबेडकरवादी छात्र एवं युवाओं का राष्ट्रीय स्तर का पहला और सबसे बड़ा संगठन है। निःस्वार्थ भाव, त्याग और समर्पण के सिवाय कोई भी सामाजिक आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। समाज के अंदर सामाजिक चेतना को जगाना और उनको सामाजिक आंदोलन के लिए तैयार करने का काम नसोसवायएफ के छात्र और युवा करेंगे। निजी क्षेत्र में आरक्षण दलित-आदिवासियों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है। आने वाले समय में दलित-आदिवासियों को निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं मिला तो फिर से हम इस देश में गुलाम हो जाएंगे और इस बार हमें कोई बचाने नहीं आएगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण हमारे लिए करो या मरो की लड़ाई है।

इस राष्ट्रीय चिंतन बैठक का संचालन बालाजी कोंडामंगल ने किया। इसमें राजस्थान से भंवर भादु, अशोक कुमार, गांविद धुंबड़ा, मध्यप्रदेश से प्रताप सिंह अहिरवार, सुशील बरखने, हेमंत उपाध्याय, उत्तर प्रदेश से रवि प्रकाश, संजय राज दिल्ली से अजय राज, कमल राजौरा, महाराष्ट्र से के. बालाजी, स्वप्निल मूले, नागेश सोनूले, पश्चिम बंगाल से सुदेब विश्वास आदि छात्र एवं युवा प्रतिनिधियों ने इस राष्ट्रीय चिंतन बैठक में भाग लिया।

...

पदोन्नति में आरक्षण बिल व अन्य समस्याओं का समाधान संयुक्त ताकत दिखाने से होगा - उदित राज

ऑल इंडिया डिफेन्स एस.सी. /एस.टी. एम्पलाईज फेडरेशन एवं सचिवालय एवं अलाईड आफिसेस एस.सी./एस.टी. एम्पलाईज फैडरेशन की ओर से श्री नेतराम ठगेला की अध्यक्षता में मोदी सरकार को देने के लिये दलित एजेण्डा तय करने व नवनिर्वाचित मेयरो एवं सांसदों का स्वागत समारोह का आयोजन दिनांक 01 जून 2014 को गांधी शांति प्रतिष्ठान, दिल्ली में सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम प्रारम्भ करते हुये डॉ. उदित राज, सांसद ने कहा कि बिना त्याग और संघर्ष के किसी भी समाज को कुछ नहीं मिला। 1997 में पांच आरक्षण विरोधी आदेश जारी होने के बाद आयकर से मैं, डिफेन्स व सचिवालय से श्री नेतराम ठगेला समेत विभिन्न कार्यालयो में कार्यरत कर्मचारी नेताओ ने मेरे नेतृत्व में परिसंघ बनाया जिसमें सभी कर्मचारी अधिकारियों ने साथ दिया। हमारे अथक प्रयासों से तीन आरक्षण विरोधी आदेश वापिस हुये थे। सांस्कृतिक आन्दोलन हमने चलाया तभी अनुसूचित जाति में उपजाति की बात मायावती जी ने प्रारम्भ कर दी उसके बाद आन्दोलन के कुछ साथी परिसंघ छोड़कर चले गये।

आज मैं भारतीय जनता पार्टी से सांसद बना हूँ, पर कुछ समय बाद मंत्री भी बन सकता हूँ। मंत्री या सांसद बनने से सामाजिक परिवर्तन नही होगा उसके लिये आन्दोलन चलाना होगा। मैं अकेला बहुत कुछ नहीं कर सकता, सफलता के लिये आप लोगों को नेतराम ठगेला की तरह मेहनत करनी होगी। इसके साथ साथ छोटी छोटी संस्थाओं के पृथक प्रयासों से बड़ा आन्दोलन नहीं बनता इसलिये संस्थाओं का कन्फेडरेशन से ऐफिलियेशन कराना होगा। नवम्बर की रैली को एतिहासिक बना दो तभी आरक्षण कानून और पदौन्नित में आरक्षण मिल पायेगा। डिफेन्स, सचिवालय फैडरेशन ने इस प्रकार का कार्यकम करके आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिये प्रयास किया इसके लिये यह टीम बधाई की पात्र है।

इससे पूर्व कार्यकम एवं फैडरेशन के अध्यक्ष श्री नेतराम ठगेला, महासचिव अनुसूचित जाति/जनजाति के संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ ने अपना मांग पत्र रखते हुये कहा कि जिस प्रकार से परिसंघ के अध्यक्ष डॉ उदित राज के नेतृत्व में आरक्षण विरोधी आदेश संविधान में संशोधन करवाकर वापिस करवाये थे। उसी भाव से आज पदोन्नित में आरक्षण उच्चतम स्तर (सचिव, डी.जी., बोर्ड आफ डायरेक्टर आदि) तक देने के लिये कानून बनाने की मांग की। इसके अतिरिक्त निम्न मांगे भी रखी।

(ख) सभी क्षेत्रों में (स्पेशलिस्ट इन्सीट्यूट समेत) आरक्षण दिलाने के लिये संसद में लाये गये कानून को दुबारा लाकर पास किया जाये।

(ग) अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनो को सामान्य संस्थाओं की भांति मान्यता दी जाये।

(घ) ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके बैकलाग वेकेन्सी भरी जाये।

(ड) सभी के लिये समान व उच्च स्तर की शिक्षा 12 वीं तक निःशुल्क की जाये।

इस अवसर पर श्री योगेन्द्र चन्दोलिया, मेयर उत्तरी दिल्ली ने कहा कि नगर निगम अपनी पांच सम्पतियॉ बेच देगी मगर 6000 कर्मचारियों को नियमित करके समाज का भला करके रहेंगे। श्री खुशीराम, मेयर दक्षिण दिल्ली ने कहा कि हम समाज का काम करते हैं मगर समाज को भी तो हमारा साथ देना चाहिये। श्रीमति मीनाक्षी, मेयर पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कहा कि पार्टी ने मुझ जैसी आम कार्यकर्ता पर विश्वास करके टिकट दिया, मेरे समाज ने पूरा साथ देकर भारी बहुमत से जिताया। अब मुझे मेयर बनाया गया है, जिसके लिये मैं अपने समाज एवं पार्टी की दिल से आभारी हूँ। भव्य अभिनन्दन करने के लिये सभी नेताओं ने श्री ठगेला व उनकी टीम को धन्यवाद दिया।

डॉ0 उदित राज को सम्मानित करते हुए परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव, नेतराम ठगेला साथ में, खुशीराम - मेयर साउथ दिल्ली व अन्य

6. श्री सुरेश तितोरिया, पूर्व विधायक (उ.प्र.), ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित समाज की इतनी अधिक आबादी होने के बाबजूद उनका अपमान हो रहा है। उन्होने फेडरेशन के संघर्षो के साथ अपनी एकजुटता दर्शाई। श्री अंगद धारिया, अध्यक्ष आगरा महानगर भारतीय लोकदल (पूर्व पार्षद एवं पूर्व चैयरमैन, भूमि समिति) ने आरक्षण हेतु आन्दोलन में पूरा साथ देने की घोषणा की। इस अवसर पर श्रीमति उर्मिला मलावालिया, पार्षद दक्षिण दि.न.नि., श्रीमति ममता राठौर, निगम पार्षद, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, इंजी. के.पी. सिंह, इन्जीनियर इन चीफ, दिल्ली नगर निगम, श्री मोहन सिंह महेन्दवारिया, (पूर्व चैयरमैन, नजफगढ जोन, दिल्ली नगर निगम), इंजी. एम.सी. टी. परेवा, मुख्य अभियन्ता, दिल्ली सरकार, डा. नाहर सिंह, संयुक्त निदेशक, दिल्ली सरकार, श्री रोहताश वन्खड, अवर सचिव, मानव संसाधन मंत्रालय, यशपाल, अवर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, सुधीर कुमार, अनुभाग अधिकारी, सामाजिक न्याय मंत्रालय, श्री डी.पी. सारिया, (कस्टम), श्री आर.के. मीना (ए.एफ. एच.क्यु.), श्री पूरनमल बेमाड (दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल), श्री महेन्द्र तंवर, ट्रस्टी सामाजिक उत्थान पत्रिका, श्री सूबे सिंह महेन्द्रा (डी.डी. ए), श्री एन. नरेन्द्र (बी.डी.एल., हैदराबाद), श्री आर.आर. वासनिक (आर्डि. फैक्टरी, चान्दा, महाराष्ट्र), श्री आर.के. पासी (डी.जी.क्यु.ए. ,जबलपुर), श्री बी.एन. राय (राईफल फैक्टरी, कोलकता), श्री आनन्द कुमार, आर्डि. फैक्टरी, मुरादनगर, श्री कुरिल, ई.एम.ई. वर्कशॉप, आगरा (यु.पी.), श्री राजकुमार मल्होत्रा (राजस्थान), श्री निरोती लाल महामना, श्री अशोक कुमार ठगेला, श्री मनोज बडसीवाल आदि प्रमुख रुप से उपस्थित थे।

...

डॉ0 उदित राज का बदायूं दौरा

3 जून, 2014 को डॉ0 उदित राज, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री कल्याण सिंह, श्री रामेश्वर चौरसिया एवं श्री सरोज पांडे ने बदायूं का दौरा किया, जहां पर दो लड़कियों का बलात्कार करके पेड़ से लटका दिया गया था। ऐसी घटनाएं दलितों एवं कमजोरों की महिलाओं व लड़कियों के साथ ज्यादा होता है। मृतक के घर वालों को 5-5 लाख रूपये की राशि भी पार्टी की ओर से दी गयी। उनके घर वालों से पूछने पर पता लगा कि धमकियां लगातार जारी हैं कि अभी सरकार तीन साल की और है। इसका मतलब यह है कि घर वाले शांत बैठ जाएं और दोषी आज़ाद घूमें। यह कोई अकेले की घटना नहीं है, उस इलाके में और बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है। उन्हें उठा ले जाते हैं और दुष्कर्म करने के बाद छोड़ जाते हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इतना आतंक है कि लोग मुंह नहीं खोलते। अगर ऐसा करें भी तो पुलिस कार्यवाही नहीं करती और अंत में दोहरी सजा मिलती है।

जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, दोषी पुलिस और नेताओं को ही ठहराया जाता है। दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग तो होती ही है। इलैक्ट्रानिक मीडिया की सक्रियता से कुछ वारदातों में त्वरित कार्यवाही होती है। विपक्ष को तो मानो एक सुनहरा आवसर मिलता है और खूब राजनीति होती है। आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो जाता है। कई दिनों तक सुर्ख़ियों में ऐसी घटनाएं रहती हैं और अंत में कानून-व्यवस्था खराब होने से घटना को जोड़ दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने लोक सभा में कहा कि बलात्कार जैसी घटना पर राजनैतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं करना चाहिए। यह एक गंभीर समस्या है। इसका समाधान केवल कानून के जरिए ही नहीं हो सकता बल्कि सामाजिक सुधार करना होगा। हमें सोच बदलनी होगी जो सरकार नहीं कर सकती। जो नारीवादी ताकतें हैं और वे लोग जो केवल इसका राजनैतिक समाधान में यकीन रखते हैं, वे अपना नजरिया बदलें और अपने घर, पड़ोस और रिश्तेदारों से शुरु करें। बेटी बेटा से जीवन में कम उपयोगी है और इसके लिए सामाजिक परंपराएं जिम्मेदार हैं। वह दाह संसकार नहीं कर सकती। खेती और व्यापार में उससे खास सहयोग नहीं मिलता। लड़ाई-झगड़ा होने पर कोई काम नहीं आती। श्राद्ध और पिंड महिला नहीं कर सकती। ज्यादातर महिलाएं बाहरी काम-काज को नहीं कर सकती। घर वालों पर उनकी सुरक्षा का स्वयं बोझ होता है। शादी के बाद मां-बाप का सहारा नहीं होती। हमने इस तरह की परंपराएं और सामाजिक व्यवस्था बना रखी है, जिससे बेटी से वह सहयोग और सुरक्षा नहीं मिलती जो बेटा से। इस समस्या को हल करने के लिए सामाजिक स्तर पर भी प्रयास करना होगा न कि केवल कानून-व्यवस्था के माध्यम से।

5-5 लाख रूपये की राशि पीड़ित परिवार को सौंपते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह, डॉ0 उदित राज व अन्य

....

दलित राजनीति की नई दिशा

डॉ0 उदित राज

पहली लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ था। उस समय दलित राजनीति कोई खास नहीं थी। दलितों व आदिवासियों में वोट की कीमत का अहसास नाममात्र ही था। हालांकि उस समय बाबा साहब डॉ0 भीमराव अंबेडकर जीवित थे, फिर भी इस समाज में जागृति का बड़ा अभाव था। डॉ0 भीमराव अंबेडकर स्वयं भी चुनाव हारे। समय बीतने के साथ-साथ समाज में जागृति आती गई और दलित राजनीति का प्रादुर्भाव धीरे-धीरे आगे बढ़ना शुरु हुआ।

महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अस्तित्व में आई, लेकिन उसकी भी सफलता आंशिक ही रही। 1960 के दशक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित-मुस्लिम गठजोड़ आंशिक रूप से ही सफल रहा। वर्ष 1993 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन से दलित राजनीति के एक नए युग की शुरुआत हुई। हालांकि यह अलग बात है कि यह गठबंधन बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि बहुजन समाज पार्टी ने एक नया प्रयोग किया और सवर्णो को भी उम्मीदवार बनाया गया। इसके पीछे सोच यही थी कि उनके अपने समाज का वोट तो है ही साथ में यदि उन्हें दलित समाज का भी वोट मिल जाता है तो निश्चित जीत की स्थिति में पहुंचा जा सकता है।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश में दलित व सवर्ण समीकरण ने वर्ष 2007 में एक बड़ी सफलता की इबारत लिखी, लेकिन वह वर्तमान लोकसभा चुनावों में ढह गया। आज प्रश्न यह है कि क्या अकेले दलित वोटों से मुख्यधारा की राजनीति में आया जा सकता है और बिना राजनीतिक मुख्यधारा में आए क्या अपने पक्ष में नीतियां बनवाई जा सकती हैं?

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से राजनीतिक ध्रवीकरण 16वें लोकसभा चुनाव में हुआ उससे न केवल क्षेत्रीय समीकरण प्रभावित हुए, बल्कि दलित राजनीति भी। मुझे भी यह अनुमान नहीं था कि दलित राजनीति को इतना तगड़ा झटका लगेगा। इतनी समझ जरूर आ गई थी कि मुख्यधारा की पार्टी से बिना जुड़े दलितों, आदिवासियों व वंचितों के लिए नीतियां बनाई नहीं जा सकती हैं। मात्र पहचान बनाना अब काफी नहीं है, बल्कि भागीदारी चाहिए। भागीदारी से देश का सर्वांगीण विकास होगा और इससे खुशहाली व राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी। शुरु में मेरे साथियों को झटका सा लगा, जब ऐसा प्रस्ताव रखा गया, लेकिन अंततः उन्हें मैं अपनी बात समझाने में कामयाब रहा और 24 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। यह विचार मंथन अक्टूबर, 2013 से ही चल रहा था और संतोष की बात यह है कि चुनाव परिणाम ने हमारी सोच पर मुहर लगा दी। दलितों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड समर्थन दिया। इनके झुकाव को बहुत सरलता से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक आशा और विश्वास इसके पीछे है।

इस संदर्भ में नरेंद्र मोदी ने 20 मई को संसद में यह सही कहा कि लोगों ने वोट आशा और विश्वास को दिया है।

परंपरागत दलित राजनीति अब थक गई है। केवल मान-सम्मान की बात कहने से भागीदारी व आत्मनिर्भरता नहीं मिलने वाली है। दलित राजनीति का मुख्य प्रतीक बनी मायावती दलितों को वह भी नहीं दे रही हैं, जिसके लिए वे विशेष रूप से बसपा से जुड़े। दलित बुद्धिजीवियों में भारी निराशा है कि आरक्षण की वजह से जो भागीदारी पहले मिल रही थी, उसमें भी कटौती होती चली जा रही है। नई आर्थिक नीति के कारण तमाम रोजगार-व्यवसाय के अवसर पैदा हो रहे हैं, लेकिन दलितों-आदिवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस दोनों में उदासीनता आई। इनका वोट जब क्षेत्रीय दलों में जाने लगा तो ऐसी स्थिति में इनके लिए केंद्र सरकारों की कुछ करने की इच्छाशक्ति भी कमजोर हुई।

इस बार के लोकसभा चुनाव में दलित वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला, इसलिए इसका फल भी उन्हें जरूर मिलना चाहिए। गत 2 मार्च की लखनऊ रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाला दशक पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों व वंचितों का होगा और इसका असर व्यापक तौर पर हुआ।

बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में 19.6 प्रतिशत वोट मिला, जबकि राज्य में दलितों की आबादी 22 प्रतिशत है। मायावती ने 17 मई को कहा कि उनका दलित वोट खिसका नहीं है जो कि झूठ है। वह उन्हीं को टिकट देती हैं, जिनकी जाति का अच्छा-खासा वोट होता है। बहुजन समाज पार्टी के ताकतवर उम्मीदवारों का वोट फिर कहां गया? सच्चाई यह है कि इस बार अच्छा-खासा दलित वोट भारतीय जनता पार्टी में गया है। मायावती मनोवैज्ञानिक युद्ध के माध्यम से दलितों को भ्रमित करके अपना जनाधार बनाए रखना चाहती हैं। 20 मई को जिस तरह से संसद में नरेंद्र मोदी ने दलितों व गरीबों के उत्थान की बात कही, उससे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि उनकी सरकार इन्हें भागीदारी देगी। ऐसा होना अब संभव प्रतीत हो रहा है, इसलिए दलित मुख्यधारा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जरूर आएंगे।

अब भारतीय जनता पार्टी की वह छाप नहीं रह गई है कि यह सवर्णो की पार्टी है। यदि हम अपने समाज को जोड़ते हैं तो इस पार्टी का दिल छोटा नहीं है और वह दलितों को पूरा सम्मान देगी। दूसरी सबसे अच्छी बात यह हुई है कि सवर्ण व दलित के बीच जो खाई बढ़ती जा रही थी, अब वह कम हुई है और मुझे विश्वास है कि आगे और भी अच्छा होगा। जिस पार्टी का अंतिम लक्ष्य यह हो कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बने तो यह स्वाभाविक है कि वह हर वर्ग को मान-सम्मान व भागीदारी दे। राष्ट्रीयता और कला-संस्कृति का बचाव तभी हो सकता है, जब राजनीतिक सत्ता पर कब्जा हो। मेरे विचार से भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि देश के दलितों को मुख्यधारा की राजनीति में भागीदारी देकर न केवल अपने राजनीतिक, बल्कि सामाजिक जनाधार को भी मजबूत करे, ताकि वह राष्ट्र निर्माण में और अधिक सशक्त भूमिका निभा सके।

– दैनिक जागरण में 31 मई 2014 को प्रकाशित।

...

भाजपा के पक्ष में राष्ट्रीय स्तर पर 4 अम्बेडकरवादी चेहरे

डॉ0 उदित राज

रामविलास पासवान

रामदास आठवले

इन्द्रेश गजभिये

रमेन्द्र प्रसाद

दलित आंदोलन, बौद्ध और अम्बेडकरवादी मिशन का जमीनी कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में भी अपनी पहचान, मुकाम और उपलब्धि हासिल करने वाले चार प्रमुख नेता डॉ0 उदित राज, श्री राम विलास पासवान, श्री रामदास आठवले एवं श्री इन्द्रेश गजभिये इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में राष्ट्रीय स्तर पर सामने आ गए हैं। पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आठवले रिपब्लिकन पार्टी (अ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन दोनों नेताओं ने भाजपा से गठबंधन किया है। यह दोनों नेता भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हुए हैं जबकि गजभिये डॉ0 अम्बेडकर जन्मभूमि महू संथान दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और डॉ0 उदित राज, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये दोनों भाजपा में शामिल हुए हैं।

यह सभी पूर्व के समय में कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के निकट रहे हैं, शामिल रहे हैं। किन्तु जैसा कि अम्बेडकरवादियों के साथ कांग्रेस पार्टी का शुरु से बर्ताव रहा है, जिसने अपने राजनैतिक लाभ के उपरांत पर काटने का और छवि को धूमिल करने का काम किया है, उन्हें न तवज्जो एवं अपमान के साथ अन्याय करके हासिये पर रखा है। कांग्रेस ने, बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर विरोधी मानसिकता की धारा एवं पृष्ठभूमि के नेताओं को हमेशा सिरमौर बनाकर पार्टी में दलित नेताओं के रूप में उन्हें मुकुट बांधने का काम किया है, इन कारणों के चलते, कांग्रेस अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारते गई है तथा कांग्रेस देश में दलित अम्बेडकरवादियों की दुश्मन नम्बर वन बनकर अपने दलित जनाधार को खत्म करती रही है।

कांग्रेस ने अपनी मानसिकता में यह मुगालता पाल लिया था कि बौद्ध अम्बेडकरवादी, दलित नेताओं को चाहे जितना सताओ किन्तु वे कभी भी कथित हिन्दूवादी भाजपा में या भाजपा के साथ समर्थन में जाने वाले नहीं हैं। कांग्रेस यह मानकर चल रही थी कि बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म का त्याग किया था इसलिए हिन्दूवादी भाजपा दलितों की दुश्मन के रूप में सर्वदा ही बनी रहेगी। शायद कांग्रेस ने इस तथ्य या सच्चाई की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया या वह भूल गई थी कि आज के नये दौर में दलित अम्बेडकरवादी समुदाय के नेता कार्यकर्त्ता अब रोटी, कपड़ा और मकान की लड़ाई को उतनी प्राथमिकता से नहीं लड़ रहे हैं, जितनी प्राथमिकता से वे अब इंसाफ सम्मान और सत्ता में भागीदारी की लड़ाई को इस दौर में पूरे देश भर में लड़ रहे हैं।

इन चारो दलित अम्बेडकरवादी नेताओं के भाजपा के पक्ष में जाने से कांग्रेस की कुटिल मानसिकता का माईन्ड सेट मुगालता टूट गया है, जिसके कारण एवं ऐसे अनेक कारणों से देश में भाजपा को सत्ता तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है, देश में पार्टी का विस्तार हो रहा है तथा भाजपा को भी अपनी छवि में परिवर्तन करते हुए अपनी परम्परागत मानसिकता को बदलते हुए बड़े दिन और बड़े दल के साथ सभी वर्गों एवं तबकों की पार्टी बनने का सुनहरा मौका हासिल हुआ है। इस तथ्य की स्वयं नरेन्द्र मोदी ने भी घोषणा कर दी है।

उपलब्धि : डॉ0 उदित राज

डॉ0 उदित राज का सामाजिक एवं राजनैतिक सफर लगभग 18 वर्षों का है। उत्तर प्रदेश उनकी जन्मभूमि है। उनका पूर्व का नाम राम राज था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपना नाम उदित राज रखा है। 10 वर्ष पूर्व उन्होंने आयकर विभाग में कमिश्नर की नौकरी छोड़कर राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश किया है। वे प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली सरकार की राष्ट्रीय एकता परिषद में सदस्य भी रहे हैं। वे बसपा के संस्थापक कांशीराम जी के निकट भी रहे हैं। वे अनुसूचित जाति, जन जाति, कर्मचारी-अधिकारी परिसंघ के संस्थापक अध्यक्ष हैं। पदोन्नति में आरक्षण दिलाने के मुद्दे पर भारत सरकार से तीन संशोधन आदेश उनकी रैली आंदोलन के दबाव के कारण जारी हुए हैं। वर्ष 2006 में उन्होंने दिल्ली में बौद्ध धर्म की दीक्षा का ऐतिहासिक एवं विशाल पैमाने पर दलित धर्मांतरण कराया हैं। वे वॉयस ऑफ बुद्धा समाचार पत्र के संपादक भी हैं व अनुसूचित जाति जन जाति को निजी क्षेत्र में आरक्षण दिलाने के लिए देश भर में लगातार मांग एवं आंदोलन करते आ रहें हैं। दिल्ली की आरक्षित लोक सभा सीट, उत्तर-पश्चिम दिल्ली से सांसद हैं।

उपलब्धि : रामविलास पासवान

राम विलास पासवान का सामाजिक एवं राजनैतिक सफल लगभग 40 वर्षों का है, बिहार उनकी जन्मभूमि है। उनकी अम्बेडकरवादी के साथ लोहियावादी की पहचान है। वे अनेक बार सांसद तो रहे ही हैं, एक बार उन्होंने सर्वाधिक वोटों से लोक सभा चुनाव जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वे भारत सरकार में रेल, संचार, इस्पात एवं सामाजिक न्याय मंत्रालय के अलावा अनेक मंत्रालयों के मंत्री रहे हैं, वे प्रधानमंत्री गुजराल के समय लोक सभा में सदन के नेता भी रहे हैं। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय पिछड़े वर्ग के लिए बनाये मण्डल आयोग के विरोध का मुकाबला करने के लिए पासवान की दलित सेना ने अहम भूमिका निभाई थी। केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री के रूप में उन्होंने दलित वर्ग के धर्मांतरित बौद्धों को अनूसूचित जाति का आरक्षण देने के लिए संसद से कानून बनवाया था तथा भारत सरकार में डॉ0 अम्बेडकर फाउंडेशन की स्थापना की थी। वर्तमान में वे भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं।

उपलब्धि : रामदास आठवले

श्री रामदास आठवले का समाजिक-राजनैतिक सफर लगभग 30 वर्षों का है। महाराष्ट्र उनकी जन्मभूमि है। वे दलित पैंथर संगठन के संस्थापक में से एक हैं। दलित अम्बेडकरवादी आंदोलन चलाने वाले नेता और अम्बेडकरवादी के रूप में उनकी पहचान है। वे महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, तथा दो बार लोक सभा के सांसद रहे हैं। वे रिपब्लिकन पार्टी को पूरे देश में विस्तारत करने में लगे हैं। केन्द्र सरकार में उनका नाम अनेक बार मंत्री बनने के लिए चलता रहा है, किन्तु कहा जाता है कि प्रभावशाली नेता शरद पवार के विरोध के कारण वे केन्द्र सरकार में मंत्री नहीं बन पाये हैं। महाराष्ट्र राज्य में, नागपुर इलाके के विदर्भ राज्य को अलग राज्य बनाने की मांग को उनका खुला समर्थन है। वर्तमान में भाजपा-शिवसेना ने उन्हें राज्य सभा का सांसद बनाया है।

उपलब्धि : श्री इन्द्रेश गजभिये

श्री इन्द्रेश गजभिये का सामाजिक राजनैतिक सफर 34 वर्षों का है। मध्य प्रदेश उनकी जन्मभूमि है। उन्होंने डॉ0 अम्बेडकर की जन्मस्थली दिल्ली को देश व दुनिया में पहचान एवं सम्मान दिलाया है। वे डॉ0 अम्बेडकर की जन्मभूमि महू संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष तथा दिल्ली में स्थित डॉ0 अम्बेडकर परिनिर्वाणभूमि (निधनस्थली) कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे एनडीएम (नेशनल दलित महापंचायत) दिल्ली के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जन्मभूमि महू में भव्य स्मारक का निर्माण कराने में, राज्य शासन की ओर से जन्मस्थली में प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को डॉ0 अम्बेडकर महाकुंभ का आयोजन लागू कराने में, महू का नाम बदलकर नया नाम 'डॉ0 अम्बेडकर नगर' कराने में उनकी बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के समय उन्होंने राजधानी भोपाल में डॉ0 अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा लगाया है। डॉ0 अम्बेडकर नगर महू में डॉ0 अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान की स्थापना कराई है। अब इस संस्थान को वे डॉ0 अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनाने की परिणाममूलक कार्यवाही कर रहे है। उनके प्रस्ताव एवं प्रयास से ही सॉची में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बुद्धिष्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जो ऐतिहासिक उपलब्धि है। वे भारत सरकार के डॉ0 अम्बेडकर फाउंडेशन एवं दूर संचार कमेटी में सदस्य रहे हैं। वे मध्य प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य राज्यमंत्री दर्जा तथा म.प्र. सरकार के राज्य अनूसूचित जाति वित्त निगम में दो बार चेयरमैन के पद पर उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहा है। दिल्ली में स्थित डॉ0 अम्बेडकर की परिनिर्वाणभूमि को राजघाट जैसा सम्मान और दर्जा दिलाने वे पिछले दस वर्षों से देश भर में और दिल्ली में आंदोलन चला रहे हैं, रैलियां कर रहे है। इसमें केन्द्र सरकार ने परिनिर्वाण स्थल पर दो सौ पन्द्रह करोड़ की लागत से भव्य स्मारक बनाने की मांग मंजूर कर ली है। वे देश भर में जाने माने प्रखर अम्बेडकरवादी वक्ता हैं तथा अम्बेडकरयुग मासिक पत्रिका के सम्पादक हैं। वे भाजपा में अनुसूचित जाति मोर्चा संस्थान संवाद के राष्ट्रीय प्रभारी भी हैं और तमिलनाडु राज्य के प्रभारी हैं।

....

SC/ST Reservation in J & K

Jammu 01-06-2014 : Today a large number of followers and those benefitted by Reservation in J&K gathered and paid homage to Shaheed Bhagat Amarnath on his 44th shaheedi Diwas in a program organised by state unit of All India Confederation of SC/ST/OBC Organisations J&K. A documentary on life of bhaghat Amarnath was also shown to the gathering.

While addressing the gathering, Sh R. K. Kalsotra, State President of the Organisation apprised the audience that the son of soil, Shaheed Bhagat Amarnath was born on 1928 in village Champa near Batote Tehsil/Distt. Ramban in a scheduled caste family. After completing his school education, he dedicated and devoted himself for social cause exclusively for downtrodden. Since his childhood, he was deeply and highly concerned about the worst plight of the oppressed and exploited people denied human rights. He was very much committed and determined to sacrifice his life for the persecuted, victimised, discriminated, exploited and neglected downtrodden masses. In order to uplift and emancipate the depressed classes, he came to Jammu with an explicit motive, aim and objective to secure justice for Dalit samaj. He came into contact with some Jammu based Dalit leaders i.e Babu Parmanand, Babu Milkhi Ram, Bhagat Chajju Ram, Pashori Lal and Mahasa Nar Singh. During 1970 there was a great resentment among Dalit Samaj for denial of Reservation Rights by unjust and hostile state government. Despite of implementation of reservation for S/C in Central Govt and the other state govts.. by Baba Sahib Dr. B. R Ambedkar in capacity of 1st Law Minister of India, the J & K state govt. was still reluctant to implement it. Shaheed Bhagat AmarNath took very serious and comprehensive note of the malafide intention of the state govt and intensified his agitation in the entire Jammu province by leading many processions, demonstrations, public meetings for the expeditious redressel of core issue of Reservation. Though an ultimatum and deadline was given to state govt to take drastic and extreme step of fast unto death yet hostile and callous attitude of state govt remained adamant. Consequently, Dalit leaders of that time decided to go on fast unto death to concede the major demand of reservation implementation along with certain core issues. Shaheed Bhagat Amarnath voluntarily offered himself for the supreme sacrifice and resolved to observe silence and subsequently sat on fast unto death . On 21-05-1970 in Karkan park in front of civil secretariat. His health condition deteriorate despite efforts by prominent physician of that time because Bhagat sahib refused to take any medical treatment and son of the soil Bhagat Amarnath achieved martyrdoom on 1st june 1970 and became " Martyr of Reservation". With his supreme Sacrifice the reservation was implemented and in this way he wrote the chapter of reservation with his sacrifice. Shaheed Bhagat Amarnath was an emancipator, great revolutionary, socialist and champion of dalit samaj. He was a political personality with a spotless image. He is no doubt a hero of reservation as well as Martyr of social justice & he is being remembered as Mini Ambedkar of j&k.

J & K Confederation members paying homage to Shaheed Bhagat Amarnath

Kalsotra further added that they warned the Coalition partner govt in March month to rectify their wrong reservation implementation in which their unemployed youth is ignored in getting reservation rights in Rebher talim, zeherat, sehat. Ad hoc, temp appointments, toto implementation of Mandal commission report, dilution of ST status, and they did not rectified and have faced defeat in the parliament election. Now again they have not protected their enactment of. reservation in promotion in the j&K High Court which stayed the policy. We are continuously appraising the Govt. & reserved political Representatives to defend their policies in court and implement toto reservation otherwise in coming elections again Govt will face similar defeat.Others who spoke were both Raj Rao, Darshan bhagat, RAMESH Sarmal, Tej Ram Dogra, Sham Bassan, NARSINGH Rajwal, Roop LAL, krishan LAL Mast, Satish Kumar, Adyita and others.

National Convention of Confederation ....

Contd. from page 8.

should get share in governance in every field in which case Dalits will extend full support to BJP not only during this time but always in future.

The Confederation has been launching a relentless struggle for the last seventeen years but the desired cooperation is still lacking. Mere criticism of Brahmanism is just not sufficient. We should adopt a constructive approach and cooperate with the people who control the reins of power and resources of the country to get a share in governance for Dalits in different fields. Due to the enforcement of the new economic policy, the scope of reservation has further gone down. If the tempo of our social movement picks up, our share in governance in different fields will automatically go up. After seeing the commitment of the RSS workers, I can say that the commitment of our members stands no where as compared to theirs. During my election campaign, I found that the RSS workers reached the Shakha venue between 5 and 6 AM and after making prayers would go to each and every house in the locality for canvassing. They had made up their mind to visit every house three times for campaigning and this they did with missionary zeal which was the main reason for my victory. On the other hand, if the members of the confederation seriously introspect, it will be seen that they stand nowhere near the RSS workers. This commitment of RSS workers is worth emulating. If the Confederation members take part in a rally once a year, they think that they have done enough. I would like to see this sense of commitment of RSS workers in the members of the Confederation for the empowerment of Dalits.

The time has come to give a new fillip to the Confederation and in that sense the ensuing national convention of the Confederation which is going to be held on 6th July, 2014, at Ravindra Bharti Auditorium, Hyderabad is very important. This programme is being organized under the overall supervision of Shri K. Maheshwar Raj, State President of the Andhra Pradesh Unit of the Confederation. His contact No. is 09440508869. Another contact person is Shri B. Narsingh Rao whose mobile no. is 09441454525. I appeal to all the members to reach Hyderabad on 5.7.2014 so that they may take part in the convention. On the 7th July, 2014, prominent leaders and workers of the Confederation will hold a meeting and decide the future course of action. Members can plan their return by 7th evening and 8th July in the morning.

...

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 17 ● Issue 14 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 1 to 15 June, 2014

KNOW THE PRIME MINISTER

Dr. Udit Raj

On 6th June, 2014, the Prime Minister said in the Lok Sabha that the practice of touching feet of senior leaders will not suffice, one must work. He advised the party MPs to come to the parliament well-prepared. On 11th June, 2014, he emphasized the importance of skill-learning amongst youngsters as 60 % of our population is under 35 years of age, whilst China's population is an aging one. The Britishers established a system of bookish learning to further their own ends, as it would enable them to administer the territory better. However, since their departure, this system has not been adapted to an Indian context.

I first experienced the feet-touching culture as a young student at the Allahabad University. No learning used to take place. Student politics had reached its pinnacle. The student leader who would have the exams postponed by the longest period, would be considered most successful. As a consequence, the curriculum was lagging behind by 3 years. Education was being mocked and destroyed. Most of these student leaders were adept at touching the feet of their superiors and getting their feet touched by their inferiors. When these students would encounter a professor or a university official, they would address him as "Guru ji" and touch his feet and once they had turned their backs, they would utter cheap abuses. Also, there was no dearth of students to touch the feet of these leaders. I realized at that point of time, that the one who touches your feet, need not necessarily respect you. True regard resides within. Having said that, touching the feet of superiors is quite useful and often the means by which people become MPs and MLAs. A few days back, a Member of Parliament had revealed that he gets elected despite his poor track record in terms of nurturing his constituency as during campaigning for elections, he touches the feet of people to mollify them. This holds truer of the reserved seats. The leaders getting away touching the feet of the people do not do any work and perpetuate backwardness in the area. The Prime Minister sent out a strong signal to curb this practice and urged people to work, to engender development in the country.

The Prime Minister gave the slogan of 'Skill, Scale and Speed'. On 11th June 2014, he mentioned a past incident. An undergraduate student meant Dada Dharmadhikari, a disciple of Vinobabhave. When he was asked what he knew, he repeatedly said that he was an undergraduate. This meant that he possessed no skill to do anything. The Prime Minister said that as the Chief Minister of Gujarat, he ensured that students pursuing vocational courses were awarded the same degree as those student pursuing regular studies. In this manner, not only did skill get the honour it deserves but also furthered the interests of the nation. In the unorganized sector, 93 per cent of the work force is unskilled. This presents a major challenge. The aim of Nation Skill Development Mission is to impart skill to 500 million or 50 crore people by 2022. Given the Prime Minister's formidable will power, it shouldn't be difficult to achieve this target.

As a student, I used to wonder why here, the various branches of engineering such as Civil, Mechanical, Metallurgy and Electrical are not emerging. The first engineering college in India was established at Roorkee. Had we encouraged skilled students, they would have done many innovations and discoveries. A person working with steel is known as a blacksmith, had he been encouraged, as his European counter parts were, he would have given rise to the discipline of metallurgy. Those who built houses were given recognition and regard, leading to the emergence of Civil Engineering. In the Developed nations, professionals such as technicians, plumbers and electricians are paid by the hour and their wages equal those of educated work force. On the other hand, back home, there is a wide gap in their wages. Skill development will not only tackle the problem of unemployment but also lead to scientific and material progress.

The Prime Minister said firmly, that no parliamentarian can get away with touching feet; they will have to work hard. His words mark the beginning of a new era and culture in India. The clear message is that sycophancy will not work anymore, only development will be recognized and honoured. The need of the hour is a new political culture, wherein the people's representatives are educated and able. Consequently, they will acquire a progressive and development-oriented view point. This will allow able and diligent workers in any party to come forward. It is important to do away with the practice of taming sidekicks. If by being at the side of a big leader and providing services to him, one can get a ticket, then who will be prompted to be dutiful, conscientious and educated? Not only in order to boost employment rates but also to usher in a new political culture, it is important to be skilled. The nation has required this overhaul for quite sometime, and the Prime Minister is working towards it. The Chinese too, were a lazy lot but the cultural revolution in china pioneered by Mao Tse-Tung changed their attitude. This message leads us also in that direction. In order to achieve this goal, the common man will also have to change and aid the process. If this happens, the work culture of our country will change for the better by integrating into it the will to work hard. This has been lacking and has been expected for long.

National Convention of Confederation on 6 July at Hyderabad

Dr. Udit Raj

Most of the members of the All India Confederation of SC/ST Organizations fully understand the circumstances under which I took a decision to go to the Parliament. I have been elected to the Lok Sabha from the North West Delhi Parliamentary Constituency. My main objective in seeking election to the Lok Sabha is to ensure a share in governance for Dalits, Adivasis and the downtrodden sections of the society rather than my own ambition or satisfaction. At the time of joining Bhartiya Janata Party also, I had expressed the same commitment which will remain with me throughout my life. My mission to go to the Lok Sabha will be accomplished only if the Confederation steps up its activities. On its own, Bhartiya Janata Party got 282 seats which addressed the issues like development and good governance. No political party raised the issues like reservation in private sector and SC, ST, OBC empowerment during the election. When without raising these issues during elections, candidates and parties can reach the Parliament, then how much I can be effective in the Parliament and the party till a powerful social movement is launched. This time, the Confederation extended full support to BJP in the elections and it is my belief that it should be rewarded. Our social movement strength will work as incentive for the BJP to support our cause. Before joining BJP, I reiterated the commitment that Dalits

Contd. on page 7/-

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by N. K. Karn